

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1153
उत्तर देने की तारीख-29/07/2026

केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में रिक्तियां

1153 श्री नारायण दास गुप्ता:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है तथा उन्हें भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के कार्यान्वयन तथा प्राप्त की गई प्रगति का आकलन किया है;
- (ग) विगत पाँच वर्षों के दौरान समग्र शिक्षा के अंतर्गत आवंटित तथा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा अवसंरचना में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं में रिक्तियों का होना और उन्हें भरना एक सतत् प्रक्रिया है। यह रिक्तियां पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु, नई संस्थाओं, योजनाओं या परियोजनाओं के खुलने और छात्रों की बढ़ी हुई संख्या और मौजूदा संस्थानों में क्षमता के विस्तार के कारण अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होती हैं।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय होने के कारण, देश में अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं।

अगस्त, 2021 में, शिक्षा मंत्रालय के तहत सभी केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों (सीएचईआई) से अपने संस्थानों में बैकलॉग रिक्तियों को मिशन मोड में भरने के लिए विशेष अभियान चलाने का अनुरोध किया गया था। सीएचईआई ने अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सहित रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया। सितंबर 2022 में, शिक्षा मंत्रालय ने भी सभी सीएचईआई को मिशन मोड में रिक्तियों को भरने के लिए प्रोत्साहित किया था। अक्टूबर 2025 में, सभी सीएचईआई से फिर से मिशन मोड में सभी बैकलॉग रिक्तियों को भरने का अनुरोध किया गया है। सितंबर 2022 से, सभी सीएचईआई ने रिक्तियों को भरने के लिए मिशन मोड भर्ती अभियान शुरू किया है। दिनांक 23.05.2026 (अर्थात् पिछले रोजगार मेले की तारीख) तक, सभी सीएचईआई द्वारा मिशन मोड में 18757 संकाय पदों सहित कुल 32114 पदों को भरा गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 का कार्यान्वयन एक निरंतर और सतत प्रक्रिया है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन विभिन्न स्वायत्त संगठन नीति के प्रावधानों को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित कर रहे हैं और प्राप्त प्रगति का नियमित रूप से आकलन कर रहे हैं।

एनईपी 2020 नए भवनों के निर्माण, कक्षाओं को जोड़ने, सुविधाओं के उन्नयन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बाधा मुक्त पहुंच के प्रावधान और बेहतर साफ सफाई और स्वच्छता के माध्यम से विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भौतिक अवसंरचना को सुदृढ़ करने को प्राथमिकता देती है। समग्र शिक्षा, पीएम-श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) और पीएम-उषा (प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान) सुरक्षित और समावेशी अवसंरचना और अधिगम के माहौल के निर्माण में योगदान देने वाली कई पहलों में से हैं। इसी तरह, पीएम-पोषण और पीएम-विद्यालक्ष्मी जैसी पहल छात्रों को शिक्षा तक पहुंचने के लिए पोषण और वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं और इसका उद्देश्य प्रतिधारण सुनिश्चित करना है।

सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और स्वायत्त निकायों द्वारा दीक्षा (डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग) को अपनाने, 200 पीएम ई-विद्या डीटीएच टीवी चैनलों और रेडियो सेवाओं के संचालन, निष्ठा (नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट) के तहत शिक्षकों का बड़े पैमाने पर क्षमता निर्माण, भारतीय सांकेतिक भाषा सामग्री के माध्यम से समावेशी डिजिटल शिक्षा का विस्तार, प्रशस्त 2.0 और सुलभ शिक्षण संसाधन, और समग्र शिक्षा के आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) घटक के तहत डिजिटल अवसंरचना और प्रौद्योगिकी-सक्षम शिक्षा को सुदृढ़ करने के माध्यम से

महत्वपूर्ण प्रगति प्राप्त की है। एनईपी 2020 के उद्देश्यों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इन पहलों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

समग्र शिक्षा का उद्देश्य प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत, स्कूलों की भौतिक और तकनीकी अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विगत पांच वर्षों के दौरान समग्र शिक्षा के तहत आवंटित और उपयोग की गई निधियों का विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	आवंटित केंद्रीय हिस्सा (लाखों में)	प्रबंध के अनुसार राज्य के हिस्से सहित व्यय (लाखों में)
2021-22	34,67,173.25	43,56,183.43
2022-23	44,49,394.26	51,95,854.48
2023-24	45,64,755.29	57,13,287.32
2024-25	47,46,073.05	56,69,470.92
2025-26	47,67,633.57	58,54,423.27
कुल	2,19,95,029.42	2,67,89,219.41

शिक्षा मंत्रालय ने विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा के अवसंरचना में सुधार के लिए कई पहल की हैं। लगभग सभी जवाहर नवोदय विद्यालय (जनवि), जो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, को स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर प्रयोगशालाओं, कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट जैसे डिजिटल उपकरणों और डिजिटल अधिगम की सुविधा के लिए विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी से सुसज्जित किया गया है। डिजिटल शिक्षा को दीक्षा, पीएम ई-विद्या, ई-पाठशाला, साथी (प्रवेश परीक्षाओं के लिए स्व-मूल्यांकन परीक्षण और सहायता), स्वयम प्लस (स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव-लर्निंग फॉर यंग अस्पइरिंग माइंड्स), स्वयम एमओओसी (मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस), एनआईओएस (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग) पोर्टल, यूट्यूब चैनल, पीएम ई-विद्या डीटीएच चैनल, मुक्त विद्या वाणी रेडियो, तारा (टीचर असिस्टेंट फॉर रीडिंग असेसमेंट) ऐप, समागम पोर्टल और प्रशस्त (प्री-असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल) ऐप जैसे प्लेटफार्मों के व्यापक उपयोग के माध्यम से भी सुदृढ़ किया गया है।
